

संपादकीय

यूरोपीय यूनियन: महामारी और कड़वाहट

बैलियम की राजधानी ब्रसेल्स में चल रही यूरोपियन यूनियन की बैठक में जिस तरह के तीव्र मतभेद समाने आए हैं और जिन तीखे शब्दों के जरिये वे प्रकट हुए हैं, वह कोई सामान्य ज्ञात नहीं है। इंयू देशों की इस बैठक में आर बातों के अलावा 1800 अरब यूरो (2100 अरब डॉलर) के बजट और रिकवरी फंड पर भी बहम चल रही है। कोविड-19 से जूझते जरूरतमंद पूर्वी-दक्षिणी यूरोपीय देशों के लिए रिकवरी फंड को जरूरी माना जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से सभी देश इस पर सहमत भी थे, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई और उसमें फ्रांस तथा जर्मनी की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि रिकवरी फंड (750 अरब यूरो) का अधिक से अधिक हिस्सा (500 अरब यूरो) महामारी से पीड़ित देशों को सहायता के रूप में दिया जाए, इस पर मतभेद उभरने लगे। दक्षिण यूरोपीय देश- इटली और स्पेन इसके पक्ष में थे, लेकिन फ्रूगल (कंज्स) फोर के नाम से जैन जा रहे चार देश- ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड्स इसके बैठक विषेश में समाने आ गए।

नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बर्नार्ड रट ने साफ-साफ कह दिया कि अपनी संसद की मंजूरी के बैग्रे वे अपने देश पर कर्ज का कोई बोझ नहीं डाल सकते, वह भी इसलिए कि सदस्य देशों को कैश बांटना है। इस पर हांगरी के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि मार्क रट पुराने कम्युनिस्ट शासकों जैसा आचरण दिखा रहे हैं। निजी टिप्पणियों से भरी यह तीखी बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवाद रिकवरी फंड की मात्रा पर ही नहीं, उसके साथ जोड़ी जाने वाली शर्तों पर भी था। हाल यह रहा कि बैठक का समय बार-बार बढ़ाया जाता रहा, लेकिन सहमति की कोई सूरत बनती नजर नहीं आई। शनिवार को समाप्त होने वाली बैठक रिकवर और फिर सोमवार को भी चलती रही, लेकिन आखिर तक इसमें शामिल नेता यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि उनके बीच सहमति बन ही जाएगी।

लक्जमध्यों के प्रधानमंत्री जेवियर बैटेल ने यहां तक कह दिया कि इंयू मीटिंग्स में शामिल होने के अपने सात साल के अनुभव में ऐसा तीखा मतभेद उहोंने कभी नहीं देखा। बहरहाल, बैठक का अंत चाहे जैसा भी हो, इन चार दिनों में इसमें जो कुछ होता हुआ दिखा है वह इस मायन्यता को ध्वन्तर करने के लिए कहाँ है कि बिटेन के अलग होने के बाद इंयू का सबसे बड़ा संकट खम हो गया और अब उसे शांति तथा सहमति से चलाना मुश्किल हो गया। 1993 में इंयू का गठन राष्ट्रीय कमज़ोर पड़ने की दिशा में एक देश कदम माना गया था। दुर्निया के एक ग्लोबल विलोज बनने के सप्तांशों को इसने पंख लगा दिए थे। यूरोपीय संघरथ की यह बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन महामारी जैसे पहले वास्तविक संकट के समाने इसमें नजर आई कहुता जा सकते हैं ताकि यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि उनके बीच सहमति बन ही जाएगी।

नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट ने साफ-साफ कह दिया कि अपनी संसद की मंजूरी के बैग्रे वे अपने देश पर कर्ज का कोई बोझ नहीं डाल सकते, वह भी इसलिए कि सदस्य देशों को कैश बांटना है। इस पर हांगरी के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि मार्क रट पुराने कम्युनिस्ट शासकों जैसा आचरण दिखा रहे हैं। निजी टिप्पणियों से भरी यह तीखी बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवाद रिकवरी फंड की मात्रा पर ही नहीं, उसके साथ जोड़ी जाने वाली शर्तों पर भी था। हाल यह रहा कि बैठक का समय बार-बार बढ़ाया जाता रहा, लेकिन सहमति की कोई सूरत बनती नजर नहीं आई। शनिवार को समाप्त होने वाली बैठक रिकवर और फिर सोमवार को भी चलती रही, लेकिन आखिर तक इसमें शामिल नेता यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि उनके बीच सहमति बन ही जाएगी।